प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

जब राज्य राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का अधिग्रहण कर लेता है तो उसका परिणाम धर्म का पतन होता है।

पं.दीनदयाल उपाध्याय

वर्ष-03, विशेषांक | खवासा, शनिवार 17 जुलाई 2021 | पृष्ठ-12, मूल्य -5 रुपए

श्री देवीसिंह मैड़ा
सरपंच ग्राम पंचायत दुलाखेड़ी
श्री कालूसिंह पैड़ा
मंडल महामंत्री पेटलावद
जिला प्रभारी मंत्री श्री इंदरसिंह परमार
(राज्य मंत्री - स्कूल, शिक्षा स्वतंत्र प्रभार)
एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन
श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का प्रभारीमंत्री
बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक
शुभकामनाएं
श्री दिलीपसिंह भूरिया
सचिव ग्राम पंचायत दुलाखेड़ी
सौजन्य - ग्राम पंचायत दुलाखेड़ी

श्री हरिओम पाटीदार
बावड़ी
श्री जीवन पाटीदार
बावड़ी
जिला प्रभारी मंत्री
श्री इंदरसिंह परमार
(राज्य मंत्री - स्कूल, शिक्षा स्वतंत्र प्रभार)
एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन
श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का
प्रभारी मंत्री बनाए जाने व
जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन
शुभकामनाएं
सौजन्य - राज कंस्ट्रक्शन बावड़ी-पेटलावद

मान. गुमानसिंह जी डामोर
सांसद - रतलाम झाबुआ
दुर्गादास सिंह जी
मोटापाला
मान. इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री बनने पर
हार्दिक बधाई एवं
प्रथम नगर आगमन पर हार्दिक
स्वागत अभिनंदन
झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री
मान. इंदरसिंह जी परमार
(राज्य मंत्री - स्कूल शिक्षा एवं
सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.)
संगीता सोनी
भाजपा प्रदेश मंत्री
राजेश कांसवा
सांसद प्रतिनिधि, पेटलावद
जयवर्धन सिंह
दिपक काग
पेटलावद
** श्री कृष्ण मित्र मण्डल, श्रद्धांजली चौक, पेटलावद **

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

सुविचार

जीत और हार जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसे समानता के साथ देखना चाहिए।
अटलबिहारी बाजपेयी

वर्ष-03, विशेषांक | खवासा, शनिवार 17 जुलाई 2021 | 3

अभिनंदन...

जीवन परिचयः झाबुआ प्रभारी मंत्री इंदरसिंह परमार...

विद्यालय जीवन से स्वयंसेवक संघ से जुड़े व पहली बार 1983 में विद्यार्थी परिषद में राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर काम किया, जिसके बाद 1990 में अभाविप में विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले स्व. भेरूलाल परमार व स्व. श्रीमती रामकुंवर बाई परमार के पुत्र व शुजालपुर क्रमांक 168 विधानसभा के विधायक इंदर सिंह परमार को 30 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है।

11 श्रीनगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी निवासी शुजालपुर विधानसभा विधायक इंदर सिंह परमार का जन्म 1 अगस्त 1964 को हुआ। इंदर सिंह परमार विद्यालय जीवन से ही स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे व 1983 से 1990 तक शुजालपुर में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय होकर कार्य किया। जिसके बाद 1990 से 1996 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए क्षेत्र के धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय होकर राजनीतिक दांव-पेच सीखें। श्री परमार ने कॉलेज से बीएससी की डिग्री लेने के बाद वकालत की डिग्री भी प्राप्त की तथा सन् 2000 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य के रूप में सक्रिय होकर अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया। राजनीति में श्री परमार के हुनर को देखते हुए भाजपा ने 2004 में भाजपा संगठन जिला महामंत्री का दायित्व दिया, जिसमें श्री परमार ने 2009 तक सक्रिय होकर कार्य किया। भाजपा जिला महामंत्री बनने के बाद 2009 से 2012 तक शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष पद का दायित्व मिला, जिसका निर्वाहन पूर्ण कुशलता के साथ करने के बाद श्री परमार को 2012 में भाजपा ने प्रदेश संगठन में मंत्री का दायित्व पार्टी के द्वारा दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में दिनोंदिन अपने पैर बढ़ाते हुए श्री परमार ने 2013 में शाजापुर की कालापीपल विधानसभा क्र. 169 क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। जिसके बाद 2018 में पुनः दूसरी बार शुजालपुर क्रमांक 168 से विधायक निर्वाचित हुए। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की 15 माह की सरकार गिरने के बाद बनी शिवराज सरकार में श्री परमार को 2 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर श्री परमार को स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। जिसके बाद अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबुआ जिले की अहम जवाबदारी देकर विकास की गंगा को रफ्तार देने के लिए 30 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। आज आपके महत्वपुर्ण दायित्व को निभाकर झाबुआ जिले के विकास को गति देने के लिए झाबुआ जिले में प्रथम आगमन पर आपका पुरे जिलेवासिंयों की और से *हार्दिक स्वागत... अभिनंदन...।*

नवनियुक्त प्रभारी मंत्री का प्रथम आगमन

मुद्दों की है फेहरिस्त - उम्मीदों की किरण

जिलेवासी उम्मीदों के सफर पर है और मंजील की खुशबु आने लगी है

लंबे समय बाद मिले जिले को प्रभारी मंत्री

माही की गूंज, झाबुआ।

कांग्रेस सरकार बनने के बाद जिले को प्रभारी मंत्री तो मिला था, किंतु कुछ कर पाने के पूर्व सरकार की रवानगी ही प्रदेश से हो गई और एक बार पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री की छवि बना चुके शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी मुख्यमंत्री के पद पर हो गई। सरकार बनने के बाद कोई योजना बनती इससे पूर्व कोरोना जैसी गंभीर समस्या सामने खड़ी हो गई, जिससे लड़ते-लड़ते लगभग एक वर्ष गुजर गया। अतिआवश्यकता के लिए जिले का अस्थाई प्रभारी मंत्री हरदीपसिंह डंग को जरूर दिया गया था, किंतु उन पर सिर्फ कोरोना काल की जिम्मेदारी थी। अंततः विकास की बांट जोह रहे झाबुआ जिले को उम्मीद की किरण दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जिले की कमान प्रभारी मंत्री के रूप में इंदरसिंह परमार को सौंपी। प्रभारी मंत्री का प्रथम नगर आगमन हुआ है तो जिलेवासी पलक पावड़े बिछाकर मंत्रीजी के स्वागत को इसलिए आतुर है कि, लगभग एक वर्ष बाद जिले के विकास को गति मिलने की उम्मीदें पूरी होने वाली है। जिलेवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को प्राथमिकता से उठाकर मंत्रीजी को अवगत कराना ही हमारा आज के ***इस विशेषांक में लक्ष्य है...***

टोल टेक्स वसूली से नाराज है जिलेवासी

टोल टेक्स को लेकर हाल ही में जिले की राजनीति गर्म हो गई, तो जिलेवासियों में भी खासा आक्रोश दिखाई दिया है। कई सामाजिक, राजनैतिक संगठनों के विरोध के बाद टोल टैक्स वसूली में कुछ छुट अवश्य प्राप्त हुई किंतु टोल व्यवस्थाएं अब भी ठीक नही है। मेघनगर-झाबुआ के मध्य रातोरात लगे टोल बूथ को लेकर जिलेवासियों में भयंकर आक्रोश देखने को मिला है। सड़क बनने के लगभग 7 वर्षो बाद टोल प्रारंभ होना जिलेवासियों को नही भा रहा है। कुछ इसी तरह थांदला-लिमड़ी मार्ग का टोल चुकाने में भी जिलेवासी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे है। बताते है कि, सड़क बनने के अल्प समय पश्चात ही मार्ग की हालत खस्ता हो चुकी है। कई बार घटिया मरम्मत की जा चुकी है, परंतु सड़क की स्थिति लंबे समय तक सुचारू रखने में टोल कंपनी अक्षम ही रही है। कई बार स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने जर्जर मार्ग को लेकर टोल कंपनी को आड़े हाथो लेते हुए शिकायते तक की है, किंतु स्थिति आज भी जस के तस ही है। इसके अतिरिक्त झाबुआ-कुक्षी मार्ग की घटिया सड़क का भी टोल जिलेवासियों को चुकाना पड़ रहा है, तो पेटलावद-थांदला के मध्य लगे टोल को बंद करने से जिलेवासियों को राहत मिली है उसी तरह जिले के अन्य टोल से भी राहत मिलने की उम्मीद प्रभारी मंत्री से है। पूर्व कलेक्टर रोहित सिंह जिले की घटिया सड़क को लेकर नाराजगी भी जाहीर कर चुके है। बावजूद इसके टोल वसूली निरंतर जारी है। जिले में टोल वसूली पर अंकुश तथा टोल वसूली लायक सड़के बनने की उम्मीदे जिलेवासियों को प्रभारी मंत्री से है।

व्यवस्थित बस स्टेण्डो का है अभाव

जिले के समस्त बस स्टैण्डो की व्यवस्था लचर है। सैकड़ो बसे जिले के विभिन्न क्षेत्रो से अन्य जिलो व महानगरों के लिए संचालित होती है, किंतु लगभग समस्त बस स्टैण्डों पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ रहता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता पेटलावद तहसील मुख्यालय को बस स्टैण्ड की है, जहां श्रद्धांजलि चौक के ईर्द-गिर्द कुछेक बसे ही खड़ी रह पाती है, जिससे हर समय जाम लगा रहता है, तो दुर्घटनाएं होने की भी आशंका बनी ही रहती है। पेटलावद वासियों की नए बस स्टैण्ड की मांग वर्षो पूरानी है। कुछ समय पूर्व नए बस स्टेण्ड को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी थी किंतु समाधान अब भी कोसो दूर ही दिखाई देता है। ऐसे ही थांदला तहसील मुख्यालय का बस स्टैण्ड भी अस्त-व्यस्त ही है। पेटलावद की ओर जाने वाली बसें सड़क की साईड में ही खड़ी रहती है, तो अतिक्रमण से घिरे बस स्टैण्ड पर कई बसे जाती ही नही। कुछेक बसों के रूकने की व्यवस्था होने से यहां भी यात्रियों को परेशान होते देखा जा सकता है। जिला मुख्यालय को भी नवीन बस स्टैण्ड की सौगात मिलना है, किंतु फिलहाल ऐसी कोई योजना पर प्रशासन कार्य करता नजर नही आ रहा, तो कुछ ऐसे ही हाल राणापुर बस स्टेण्ड के भी है जहां का पहुंच मार्ग ही अपूर्ण पड़ा हुआ है।

व्यवस्थित बस स्टेण्डो का है अभाव

जिले के समस्त बस स्टैण्डो की व्यवस्था लचर है। सैकड़ो बसे जिले के विभिन्न क्षेत्रो से अन्य जिलो व महानगरों के लिए संचालित होती है, किंतु लगभग समस्त बस स्टैण्डों पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ रहता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता पेटलावद तहसील मुख्यालय को बस स्टैण्ड की है, जहां श्रद्धांजलि चौक के ईर्द-गिर्द कुछेक बसे ही खड़ी रह पाती है, जिससे हर समय जाम लगा रहता है, तो दुर्घटनाएं होने की भी आशंका बनी ही रहती है। पेटलावद वासियों की नए बस स्टैण्ड की मांग वर्षो पूरानी है। कुछ समय पूर्व नए बस स्टेण्ड को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी थी किंतु समाधान अब भी कोसो दूर ही दिखाई देता है। ऐसे ही थांदला तहसील मुख्यालय का बस स्टैण्ड भी अस्त-व्यस्त ही है। पेटलावद की ओर जाने वाली बसें सड़क की साईड में ही खड़ी रहती है, तो अतिक्रमण से घिरे बस स्टैण्ड पर कई बसे जाती ही नही। कुछेक बसों के रूकने की व्यवस्था होने से यहां भी यात्रियों को परेशान होते देखा जा सकता है। जिला मुख्यालय को भी नवीन बस स्टैण्ड की सौगात मिलना है, किंतु फिलहाल ऐसी कोई योजना पर प्रशासन कार्य करता नजर नही आ रहा, तो कुछ ऐसे ही हाल राणापुर बस स्टेण्ड के भी है जहां का पहुंच मार्ग ही अपूर्ण पड़ा हुआ है।

श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का
प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में
प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन
एवं शुभकामनाएं
जिला प्रभारी मंत्री, श्री इंदरसिंह परमार
राज्य मंत्री - स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन
श्री तोलसिंह गणावा
अध्यक्ष खवासा भाजपा मंडल
-: खवासा मंडल कार्यकारिणी :-
श्री देवीसिंह देवदा
महामंत्री
महामंत्री
उपाध्यक्ष
श्री कचरू मैड़ा
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
मंडल मंत्री
मंडल मंत्री
मंडल मंत्री
मंडल मंत्री
मंडल मंत्री
मंडल मंत्री
कार्यालय मंत्री
कोषाध्यक्ष
किसान मोर्चा अध्यक्ष
सौजन्य - तोलसिंह गणावा भाजपा मंडल खवासा

रेल लाईन अभी भी झाबुआ के लिए सपना, राष्ट्रीय राजमार्ग भी रास नहीं आ रहे

झाबुआ वर्षों से रेल लाईन के लिए टकटकी लगाए बैठे है, किंतु केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा रखी गई रेल लाईन की नीव भाजपा सरकार में भी पूर्ण होती नही दिखाई दे रही है, कारण यही कि, पर्याप्त बजट नही मिल पा रहा है। प्रभारी मंत्री जो जिले को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है केन्द्रीय मंत्रीयों से भेंटकर जिलेवासियों को रेल लाईन की सोगात जल्द दिलाने में कामयाब हो सकते है। दाहोद-इंदौर रेल परिजयोजना की लागत, बजट के अभाव में दिनो दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि उंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। जिले को इंदौर-फुलमाल फोरलेन के नाम पर एक बड़ी सौगात जरूर मिली थी किंतु कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है ही। झाबुआ से इंदौर तक बनी पुल-पुलिया के आस-पास की सड़क दब चुकी है तो टोल दरे भी सातवे आसमान पर है। ऐसी स्थिति में आवागमन करने वालो को उस स्तर की सुविधाएं नही मिल रही जितना वह टोल चुका रहे है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तरह इन रेल परियोजना को पूर्ण करने की अपेक्षा जिले को प्रभारी मंत्री से है।

स्वास्थ्य सुविधा अब भी आवश्यकता अनुसार नहीं

जिले की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से हर कोई भलिभांति परिचित है। हालांकि स्वास्थ्य महकमें के साथ जिला प्रशासन ने दोनो ही कोरोना काल में बेहतर प्रयास कर अच्छे परिणाम प्राप्त किए है, किंतु अब भी जिला स्वास्थ्य सुविधाओं की बांट ही जोह रहा है। कोरोना काल समाप्ति के पश्चात भी अब तक जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल को सीटी स्केन मशीन प्राप्त नही हो पाई है, तो ऑक्सीजन प्लांट भी नही लग पाया है। थांदला तथा पेटलावद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर जरूर आमजन के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके है। किंतु शासन स्तर से जिले के सबसे बड़े अस्पताल को अब भी यह सुविधा प्राप्त नही हो पाई। फटेहाल तो अंचल के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है। चिकित्सको का अभाव लगातार बना हुआ है तो गंभीरावस्था में मरीजों को ज्यादातर समीपस्थ प्रांत गुजरात के निजी चिकित्सकों की ओर रूख करना पड़ता है, जहां ईलाज व्यवस्था तो संतोषप्रद हो जाती है, किंतु मरीज के परिजनों का खर्च कई बार इतना हो जाता कि, उन्हे अंचल के लोगो से मदद की गुहार तक लगानी पड़ जाती है। जिले की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का ही परिणाम है कि, अब अंचल में बड़े-बड़े निजी चिकित्सालय प्रारंभ हो रहे है, जहां ईलाज तो मिलेगा किंतु गरीबों के पैसो का अतिरिक्त खर्च होगा। अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने, चिकित्सको व संसाधन आपूर्ति की आस भी अंचलवासियों को प्रभारी मंत्री से रहेगी।

अतिथि शिक्षको के भरोसे शालाएं तो महाविद्यालयों में भी सुविधाओं का अभाव

पिछड़े जिले से कहने को कई बड़े अधिकारी वर्तमान में प्रशासनिक सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में सम्हाल रहे है, किंतु शिक्षा व्यवस्था अब भी चिंतित करने वाली है। कई प्राथमिक शालाएं अब भी मात्र एक शिक्षक के भरोसे है तो अतिथि शिक्षकों के भरोसे भी अंचल का भविष्य खड़ा है। जिले के विद्यार्थी पढ़ना चाहते है किंतु शिक्षा व्यवस्थाएं अब भी नाकाफी ही साबित हो रही है। कहीं जर्जर भवन तो अधिकांश जगहों पर शिक्षको का टोटा बना हुआ है। कई ऐसे भी छात्रावास है जो स्वयं के भवन की राह ताक रहे है। अभावो में जिले का भविष्य तो बन रहा है, किंतु शिक्षा की यह डगर कांटो भरी प्रतीत हो रही है। यही नही जिले को बड़े महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज की सौगाते भी मिली हुई है, लेकिन कहीं भवन का अभाव है तो कोई प्रोफेसरों की कमी से जूझ रहा है। नए प्रभारी मंत्री से जिले का भविष्य बनने वाले विद्यार्थियों को भी आस है कि, शिक्षको, प्रोफेसरों की अब पूर्ति होगी, शिक्षा संसाधन भी पर्याप्त मिलेंगे।

नर्मदा-माही लिंक परियोजना का कार्य अब शीघ्र होने की उम्मीद

2100 करोड़ रूपयों की नर्मदा-माही लिंक परियोजना की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 योजना की मंजूरी दी थी। कार्य पुर्ण होने पर इस परियोजना से धार सहित झाबुआ जिले के कई किसानों को 2022 तक लाभ मिलना था परंतु कार्य की सुस्त रफ्तार से ऐसा नही लगता की कार्य तय समय सीमा में पुर्ण हो पाएगा। इस परियोजना में टेंडर मुम्बई की लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन और जेएमसी विलो को संयुक्त रूप से मिला है। इसकी शुरूआत मनावर तहसील के ग्राम एकलवारा से पाइपलाईन के जरिए पानी लिफ्ट कर माही नदी के उद्गम स्थल मिंडा तक लाया जाएगा। उक्त माही लिंक परियोजना से धार जिले के सरदारपुर व झाबुआ जिले की झाबुआ, थांदला, पेटलावद व मेघनगर तहसील के 202 गांव में जमीन के भीतर अलग-अलग व्यास के आकार की पाइपलाईन योजना के अंतर्गत डाली जाना है, जिससे 57 हजार 442 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों के खेतों में ग्रेविटी के माध्यम से नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए पहुंचना है। लेकिन झाबुआ जिला उक्त परियोजना के कार्य के शुरूआत की राह जो रहा है, अब प्रभारी मंत्री से उम्मीद है कि, उक्त परियोजना के कार्य को जल्द ही मुर्त रूप देकर कार्य शीघ्र शुरू करवाएंगे।

भ्रष्टाचार की बह रही गंगा

पिछड़े जिले का तमगा लिए अंचल में विकास के लिए कहने को कई योजनाएं संचालित हो रही है। शासन-प्रशासन जिलेवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अन्य जगहों की अपेक्षा विशेष राशि भी जिले के लिए जारी करता है, परंतु आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाही आने वाली राशि की बंदरबाट कर लेती। जो कोई कार्य होता भी तो उसका स्तर इतना घटिया रहता है कि, एक-दो वर्षो बाद समस्याओं से जिलेवासियों को दो-चार होना पड़ता है। जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों सहित नगरीय निकाय, राजस्व, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ऐसे विभाग जिनमें जमकर भ्रष्टाचार की गंगा बहती है। प्रभारी मंत्री से उम्मीद तो यह भी है कि, इन विभागों की ओर नजरे टेढ़ी कर भ्रष्टाचार रूपी घोड़े के मुंह में लगाम डालेंगे।

इंडोर, आउटडोर स्टेडियम भी अधर में

जिले में शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में स्वीकृत करोड़ों रुपये के खेल परिसर जिसमें इंडोर, आउट डोर खेल खेलने की व्यवस्था है, निर्मित किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुध नहीं ली गई। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार व वापस शिवराज सरकार को एक वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इन खेल स्टेडियम को संबंधित ग्राम पंचायत को हेंडओवर नहीं किया गया। जिससे वे लावारिस की तरह पड़े है और कई जगह पर असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हे नुकसान भी पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में शासन के करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद वास्तविक लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

ऐसे में नए प्रभारी मंत्री के आने से यह उम्मीद जागी है कि वे इस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे और इन खेल स्टेडियम को स्थानीय निकायों को सुपुर्दगी दिलवाकर इन स्टेडियमों में खेल गतिविधियां चालू करवाएंगे। रखरखाव का जिम्मा स्थानीय निकायों को मिलने के बाद असामाजिक तत्व इनको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे।

विकास के राह में दो विभागों के बीच अडंगा क्यों...?

वही शासन स्तर से कोई भी योजना मंजूर होती है तो यह माना जाता है कि, सभी विभागीय कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है और संबंधित योजना तय समय सीमा में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। अगर योजना एक से ज्यादा विभाग की होती है तो अन्य विभाग उसमें अडंगा लगा देते हैं और योजना अधर में लटक जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सड़क निर्माण की स्वीकृति हो तो सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के लिए वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है और वन विभाग उसमें किंतु परंतु का अड़ंगा लगाकर मामला अटका देता है और तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। जिसमें कार्य की लागत बढ़ जाती है और फिर लागत बढ़ने पर मामला वित्त विभाग के पास चला जाता है, फिर वित्त विभाग उस पर पुनः विचार करता है। ऐसे में विभागीय कार्रवाई के बीच मामला अटक जाता है और जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है और बेवजह ही कार्य की लागत बढ़ जाती है और अंततः बोझ आम जनता पर ही पड़ता है।

कुछ ऐसा ही मामला इंदौर-झाबुआ-अहमदाबाद हाईवे का है, जिसमें वन विभाग की आपत्ति के बाद माछलिया घाट के पास व फुलमाल के पास कार्य अटका पड़ा है। ऐसी ही स्थिति देश के निर्माणाधीन कई नेशनल हाईवे और सड़क की भी है। इसी तरह पीएचई विभाग व सिंचाई विभाग के बिच भी रहता है, पीएचई विभाग पेयजल योजना के तहत सिंचाई विभाग के जल स्त्रोत से पेयजल हेतु कार्य भी प्रारंभ कर देते है परंतु सिंचाई विभाग से पेयजल लाने की परमिशन व पेयजल स्त्रोत परिसर में कुप खनन की परमिशन नही देती है, नतीजन पीएचई विभाग द्वारा पेयजल योजना के तहत जो राशि खर्च की जाती है उसका लाभ आमजन को नही मिल पाता। जब एक सरकार के अन्तर्गत सारे विभाग आते है और मामला शासन स्तर से स्वीकृत होता है तो अन्य विभागीय कार्रवाई के नाम पर इतनी टालमटोल क्यों...? जबकि होना यह चाहिए कि, शासन स्तर पर स्वीकृति के साथ ही सभी विभागों की परमिशन मिल जाना चाहिए और कोई भी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए जिससे न केवल आम जनता को उसका वास्तविक लाभ मिले वरन् जनता की जेब पर ज्यादा भार भी न पड़े। प्रभारी मंत्री परमार अगर इस पर गंभीरता से विचार कर मंत्री मंडल, सीएम से लेकर राष्ट्रपति तक मुलाकात कर इसका समाधान करते है तो तय है आपके कार्यकाल में झाबुआ जिले के साथ प्रदेश की नहीं वरन् देश के विकास कार्यो को गति मिलेगी।

पलायन मुख्य समस्या, समाधान असंभव सा...

जिले की वर्षों पूरानी पलायन की समस्या जस की तस ही बनी हुई है, अपितु समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। पिछड़े जिले का तमगा लगे अंचल के गांव-गांव पलायन कर समीपस्थ राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि महानगरों में मजदूरी करने हेतु जाते रहे है। प्रशासन ने लाख हाथ-पेर मारकर स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के प्रयास किए किंतु पलायन नही रोक पाया। यही कारण है कि, पलायन ''दिन दूनी रात चौगुनी'' तरक्की की ओर है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब पलायन करने वालों के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है। एकाधिक संख्या में पलायन हेतु जाने वाले कई ग्रामीण पिछले वर्षो में हुई दुर्घटना में काल के ग्रास बने है, तो कई ऐसे भी जिनके आधे परिवार पलायन पर जाने अथवा आने के लिए हुई दुर्घटना में चल बसे। जिले में पलायन पर जाने वालो की दुर्घटना के ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें परिवार के कमाने वालों का साया ही उठ गया हो। पलायन पर जाने वाले ग्रामीणों के लिए असुरक्षित व अवैध रूप से धड़ाधड़ परिवहन किया जा रहा है। अंचल के छोटे-छोटे से गांवो से कई बसें संचालित होने लगी है। अवैध रूप से संचालित होने वाली इन बसों पर न तो प्रशासन और न ही परिवहन विभाग का किसी प्रकार का कोई अंकुश है। बस संचालकों की स्थिति यह है कि, ओव्हरलोड बसे चलाकर कुछेक वर्षो में ही लखपति तक बन गए। नए प्रभारी मंत्री से ठेठ गांव-खेड़ो में निवासरत ग्रामीण मजदूरों को यही उम्मीदें है कि, स्थानीय स्तर पर शासन कार्य दिलाए अथवा पलायन को सुगम व सुरक्षित करने के प्रयास करें।

श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का
प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में
प्रथम आगमन
पर
श्री कलसिंह भाबर
अ.ज.जा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
हार्दिक अभिनंदन
एवं
शुभकामनाएं
जिला प्रभारी मंत्री, श्री इंदरसिंह परमार
राज्य मंत्री - स्कूल, शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन
सौजन्य - शुभेच्छु शांदला क्षेत्र

मान. इन्दरसिंह परमार को झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री
बनने पर हार्दिक बधाई
एवं प्रथम आगमन पर
हार्दिक स्वागत – अभिनन्दन
सुश्री निर्मला भुरिया
पूर्व राज्यमंत्री मध्यप्रदेश
श्रीमति आरती भानुपुरिया
भाजपा जिलाध्यक्ष
मा. इन्दरसिंहजी परमार
झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री
मनोज कुमार शर्मा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मनोहर भटेवरा (मोटा भाई)
अध्यक्ष नगर परिषद
श्रीमती माया राजु सतोगिया
उपाध्यक्ष नगर परिषद
अपिल : * नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनावें * साफ सफाई का ध्यान रखे * कचरा हमेशा कचरा वाहन मे ही डाले * जलकर, भवन कर आदि कर भुगतान समय पर करे * शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय में सम्पर्क करे * जन्म -मृत्यु का पंजीयन निर्धारित समय में अवश्य करावे।
स्वच्छ भारत
स्वच्छ पेटलावद– सुंदर पेटलावद
विनित :- नगर परिषद पेटलावद जिला झाबुआ (म.प्र.)

श्रीमती राजलक्ष्मी राठौर
श्री इंदरसिंह परमार
जिला प्रभारी मंत्री
को झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं
सौजन्य –गोपाल लाला बावड़ी मित्र मंडल, पेटलावद

श्री सुखराम मोरी
श्री इंदरसिंह जी परमार को झाबुआ जिले का
प्रभारी मंत्री बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक शुभकामनाएं
सौजन्य –ग्राम पंचायत मोईचारणी विकासखंड पेटलावद

श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार (मामा)
भाजपा नेता, रायपुरिया
श्री भेरूलाल पाटीदार (मामा)
रायपुरिया
श्री इंदरसिंह परमार
को झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं
सौजन्य – लक्ष्मीनारायण पाटीदार मित्र मंडल, रायपुरिया

श्री मुकेश मेहता
जिलाध्यक्ष भाजपा
पिछड़ा वर्ग मोर्चा
श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का
प्रभारी मंत्री बनाए जाने व
जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक शुभकामनाएं
सौजन्य – एक शुभचिंतक बामनिया

श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का
प्रभारी मंत्री बनाए जाने व
जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक शुभकामनाएं
सौजन्य -ग्राम पंचायत बेगनबड़ी

श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं
सौजन्य - सुराणा डेंटल क्लिनिक एवं टीम ऑल शॉपिंग बस स्टेंड झाबुआ

श्री राजेश जी दुबे
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
श्री राजेन्द्र चुन्नु शर्मा
वरिष्ठ उद्योगपति
श्री लायनसिंह जी सौलंकी
भाजपा नेता
श्री इंदरसिंह जी परमार
को झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं
जिला प्रभारी मंत्री
श्री इंदरसिंह परमार
राज्य मंत्री - स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
एवं सामान्य प्रशासन विभाग मप्र.शासन
जिले में विकास की गंगा बहाएंगे माननीय श्री इंदरसिंह परमार जी
सौजन्य — एक शुभचिंतक, झाबुआ

पेटलावद का 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल बन सकता है स्वास्थ्य सुविधा की मिसाल

कोरोना काल मे सरकारी हॉस्पिटल के प्रति बने विश्वास को कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी

कोरोना काल के दौरान कलेक्टर मिश्रा के नेतृत्व में पेटलावद स्वास्थ्य अमले ने निभाई अपनी जिम्मेदारी

कलेक्टर सोमेश मिश्रा कोरोना काल में लगातार रहे सक्रिय।

माही की गूंज, पेटलावद।

जब भी आमजन को स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता लगती है उसका रुख निजी हॉस्पिटल की और ही होता है, कारण सरकारी हॉस्पिटल में शासन की सैकड़ों योजनाओं के साथ मुफ्त इलाज के बाद भी अव्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के साथ संसाधनों की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद नही करते। लेकिन कोरोना काल मे ये मिथक टूटता नजर आया। आधी-अधूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच कई सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधा और इलाज मिला जिससे लोगो का सरकारी अस्पतालो के प्रति विश्वास बन गया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि, इस विश्वाश को कायम रखे और सरकारी सुविधाओं से कागज पर तैयार सरकारी अस्पताल को मूर्त रूप देकर अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाए।

पेटलावद का 100 बेड का नया सिविल हॉस्पिटल बन सकता है मिसाल

बरवेट रोड पर लगभग 8 करोड़ की लागत से बना नया सिविल हॉस्पिटल जिले में कोरोना काल मे अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में क़ामयाब रहा। जिले में आए नए कलेक्टर सोमेश मिश्रा के नेतृत्व में पेटलावद स्वास्थ्य अमले ने प्रशासन और समाजसेवा सहयोग से कोरोना मरीज़ों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी एमएल चौपड़ा ने बताया कि, कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 200 कोरोना मरीज भर्ती किए गए जिसमे प्रदेश के अन्य जिलों सहित आस-पास के राज्य के भी मरीज़ यहां आकर ठीक हुए, कुल 28 लोग गम्भीर स्थिति में रेफर किए गए और 29 लोगो की जान गई जो गम्भीर हालात में कही हॉस्पिटल में जगह नही होने के कारण यहां भर्ती हुए थे। जहाँ बड़े से बड़े अस्पतालो में ऑक्सीजन की सुविधा नही थी पर यहां जनसहयोग से 17 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, कोरोना काल में बिना किसी सुविधा के लगभग 40 बेड का कोविट सेंटर शुरू किया गया, जो पूरे कोरोना काल मे न केवल मरीज़ों के लिए जीवन दायनी रहा, बल्कि बड़े आर्थिक खर्च से कई परिवार को बचाया।

इनका रहा विशेष योगदान

जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा के विशेष दिशा निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी जयपाल ठाकुर के नेतृत्व में बीएमओ एमएल चोपड़ा, कोरोना प्रभारी डॉक्टर अखलेश अरोरा, डॉक्टर गोपाल चोयल, डॉक्टर धर्मेश बघेल, डॉक्टर भरत, डॉक्टर मासूम तलेसरा, डॉक्टर आयुषी पाटीदार, आयुष विभाग के डॉक्टर दशरथ बसोड़ के साथ स्टाफ नर्स राधा जाटव, मंजुला नलवाया और चंदा कटारा ने समय-समय पर अपनी ड्यूटी अपनी जान की परवाह किए बगैर निभाई ओर कई लोगो की जान बचाई।

सरकार की मंशा अनुसार हो सुविधा तो मिलेगी पूरे क्षेत्र को अच्छी स्वास्थ सुविधा

सीएचएममो जसपाल ठाकुर, बीएमओ चौपडा कोरोना काल मे मरीज़ों का हालचाल जानते हुए।

सरकार की मंशा और प्रोजेक्ट में दी गई सुविधाओ की यदि पूर्ति की जाती है तो विकास खण्ड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार होना तय है। पेटलावद विकास खण्ड के अंतर्गत आने वाले लगभग 7 से 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कई उपस्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर स्थिति में पहुँचने वाले मरीजों को अन्य शहरों और अन्य राज्यो के लिए रेफर करना पड़ता है और कई बार समय पर इलाज नही मिलने की स्थिति में लोगो की जान तक चली जाती है। हॉस्पिटल पहुँचने वाले कई मरीज़ों को भारी आर्थिक छती उठानी पड़ती है।

ये रहेगी सिविल हॉस्पिटल में सुविधा

सरकारी प्रोजेक्ट के अनुसार पेटलावद सिविल हॉस्पिटल में 21 डॉक्टरों की टीम के साथ कुल 81 लोगो का स्टाफ रहेगा, साथ ही अन्य बड़े हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाए यहाँ मिल सकेगी। फ़िलहाल यहाँ पर कोरोना संकट में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जिसमें...

- 17 लाख की लागत से जनसहयोग से लगा ऑक्सीजन प्लांट।
- 20 लाख की लागत से विधायक निधि से प्राप्त पूर्ण सुविधा वाली एंबुलेंस, साथ ही एक पुरानी एम्बुलेंस और शव वाहन हॉस्पिटल में मौजूद हैं।
- केंद्र की और से एक और बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगना है जिसका कार्य शुरू हो चुका है।
- हॉस्पिटल में लगने वाली बड़ी मशीनरी और ऑक्सीजन प्लान्ट को बिजली नही होने की दशा में संचालित करने के लिए 8 लाख 80 हजार रूपए की लागत से 125 केवी का जरनेटर जो कि, विधायक निधि से स्वीकृत होकर कुछ ही दिन में लगने वाला है।
- हर प्रकार की जांच और किसी भी गभीर बीमारी की जांच के लिए हाईटेक लेब का लगभग सामान हॉस्पिटल पहुँच चुका है और लेब शुरू भी हो चुकी।
- हॉस्पिटल में लगभग 50 लाख की लागत से 5 बेड का आईसीयू रूम की व्यवस्था होना हैं जिसके लिए सांसद द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसका कार्य जल्द ही शुरू होना है।
- 100 बेड के सिविल हॉस्पिटल में 25 बेड पहुँच चुके हैं।
- कोरोना काल मे अलग-अलग संगठनों और समाज़सेवीयों द्वारा 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हॉस्पिटल के पास पहुँच गई, साथ ही हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन गैस के पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध हो गए हैं।
- डेंटिस विभाग की लगभग पूरी मशीनरी हॉस्पिटल पहुँच चुकी है।
- 10 लाख की लागत की डिजिटल एक्स-रे मशीन जो कि 15वे वित्त आयोग की राशि से जनपद निधि से सांसद प्रतिनिधि के प्रयासों से स्वीकृत हो चुकी हैं।
- कोरोना काल मे सिटी स्कैन मशीन हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रहा है लेकिन सोनोग्राफी जैसी मामूली सुविधा के लिए निजी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है।

जन सहयोग से लगा ऑक्सीजन प्लांट।

शासन की और से दी जाने वाली सिविल हॉस्पिटल की कई और सुविधाओं का यहाँ पहुंचना जारी है जिससे आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आमजन निजी हॉस्पिटल में होने वाले भारी भरकम खर्चे से राहत महसूस कर सकेंगे।

कमजोर पहलू: स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी रहेगी चुनोती

सरकार हर सम्भव प्रयास कर हर प्रकार की सुविधा तो मुहैया करवा देगी पर स्टाफऔर डॉक्टर्स की पूर्ति नही कर पाई तो सरकारी हॉस्पिटल के प्रति जागा विश्वास टूटने में देर नही लगेगी। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 35 के लगभग का स्टाफ है जबकि सिविल हॉस्पिटल के लिए 81 लोगों के स्टाफ होना बताया गया है। जिसमे इन सुविधाओं की दरकरार है-

- हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान में कोई नही है।
- आँखों के इलाज के लिए अभी कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नही है।
- ईएनटी डॉक्टर की कमी।
- कई प्रकार की हाईटेक मशीनो के संचालन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है।
- गर्भवती महिला का रुझान सरकारी हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रहा है लेकिन सोनोग्राफी जैसी मामूली सुविधा के लिए निजी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है।

शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ऐसे समय को देखते हुए सिटी स्कैन मशीन लगना जरूरी है।

- वाटर कूलर की व्यवस्था होना बाकी है, कोरोना के समय मरीजों ओर उनके परिजनों को खुले में रखी नान से पानी पीना पड़ा।

सिविल हॉस्पिटल पूर्ण सुविधाओं के साथ शुरु होने के सवाल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद के डॉक्टर एमएल चौपड़ा ने कहा कि, हम लगातार जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के संपर्क में है और लगातार शासन की ओर से सुविधाओं को लेकर सामग्री प्राप्त हो रही है। टीकाकरण कार्य युद्ध स्तर पर है और पेटलावद विकास खण्ड टीकाकरण के कार्य मे अपना शत प्रतिशत देने में कामयाब रहा है।

नए ऑक्सीजन प्लांट और जनरेटर के लिए तैयार फाउंडेशन।

डिजिटल लेब का सामान पहुँचा, लेब हुई शुरू, जल्द ही सभी जरूरी जांचे हो सकेगी।

गंभीर और दिव्यांग मरीजों सहित मरीज के परिजनों के लिए रहेगी लिफ्ट की व्यवस्था।

कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर पूरा अमला निपटने को तैयार है। बीएमओ चौपड़ा ने बताया कि, सिविल हॉस्पिटल में मिल रही सामग्री के अनुसार अगर डॉक्टर और पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हुए तो विकास खण्ड की स्वास्थ्य सुविधाएं ''मिल का पत्थर'' साबित होगी। कोरोना को लेकर अपना संदेश देते हुए डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि, अभी भी सुरक्षा जरूरी है, मास्क पहने, सामाजिक दूरी रखे, जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाए, सेनेटाइजर का उपयोग करे, साबुन से हाथ धोते रहें। हमारा सुरक्षित रहना ही हमारा बचाव है।

संदेश :- दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हारेगा कोरोना, जीतेगा झाबुआ

श्रीमती आरती भाबपुरिया
भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष
जिला प्रभारी मंत्री श्री इंदरसिंह परमार
राज्य मंत्री - स्कूल, शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
एवं सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन
श्री इंदरसिंह जी परमार को झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री
बनाए जाने व जिले में प्रथम आगमन पर
हार्दिक अभिनंदन
शुभकामनाएं
सौजन्य – मेघनगर, पेटलावद भाजपा कलाल मित्र मंडल

मान. इन्दरसिंह परमार
को झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री
बनने पर हार्दिक बधाई
एवं प्रथम आगमन पर
हार्दिक स्वागत – अभिनन्दन
मा. इन्दरसिंहजी परमार
झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री
विनित : बिरज पोरवाल मित्र मण्डल, घुघरी सेक्टर मण्डल सारंगी

मान. इन्दरसिंहजी परमार को
झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर
हार्दिक बधाई
एवं प्रथम नगर आगमन पर
हार्दिक – हार्दिक
वंदन – अभिनन्दन
मा. इन्दरसिंहजी परमार
झाबुआ जिला प्रभारी मंत्री
विनित : भारतीय जनता पार्टी मण्डल सारंगी

कोरोना में बच्चों का भविष्य अधर में, बिना ज्ञान के सर्टिफिकेट से नहीं होगा देश और बच्चों का भला

कोरोना में सरकार के नियंत्रण में नहीं रहे निजी स्कूल, जारी रही फीस के नाम की लूट

विकास की पटरी पर दौड़ रहे देश की रफ्तार कोविट.19 ने अचानक धीमी कर दी, खमियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ा। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि अपनों को खो कर मानसिक रूप से भी लोग बुरी तरह से टूट गए। जैसे तैसे जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी थी किए कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर कर दिया और कोरोना में सबने कुछ न कुछ खोया। वहीं देश के भविष्य को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है, जो पिछले दो वर्षों में सबसे निचले स्तर पर चला गया। जहाँ छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज तक के छात्रों को बिना शिक्षा के प्राप्त किए प्रमोशन दिया गया। सरकार की और से बच्चों के दो महत्वपूर्ण वर्ष नहीं बिगड़े इसकी व्यवस्था कर दी, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का ये निर्णय न केवल बच्चों के भविष्य, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बिना ज्ञान के बाटे गए सर्टिफिकेट से शिक्षा की नींव (1से 8) तक ए शिक्षा की दीवारें (9 से12) और शिक्षा के छत (महाविद्यालय) का स्तम्भ कमजोर हो गया है। इस स्तर पर जो शिक्षा मिलनी थी वो नही मिल सकी और अब उनके सामने इन दो वर्षों में बिना कुछ सीखे नए विषयों की चुनौती होगी। ज्यादातर बच्चे इन दो वर्षों में शिक्षा से पूरी तरह से दूर रहे है, ऐसे में आने वाले समय मे अगर शिक्षा वही से शुरू होती है मतलब पुराने पाठ्यक्रम को जारी रखा गया तो बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। हर नए पाठ्यक्रम में मिलने वाला ज्ञान पिछले पाठ्यक्रम से जुड़ा है। 10 वीं और 12वी के महत्त्वपूर्ण पड़ाव को बिना चुनोती पार करने वाले बच्चे आगे कितना और किस प्रकार का परिणाम देंगे और सरकार इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं ये देखना होगा।

पिछले दो वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ घटा यदि भविष्य में स्थिति सामान्य होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रोमोशन किए गए बच्चे अतिरिक्त क्लास के माध्यम से पिछले सत्र का महत्वपूर्ण सारांश की शिक्षा ग्रहण करे, ताकि जो शिक्षा, जिससे वो वंचित हुए है उसका थोड़ा ज्ञान बटोर कर आगे के लिए मजबूत हो सके। साथ ही जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसमें परिवर्तन कर दो से तीन भागों में बाट कर शिक्षा की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है।

शिक्षकों से हटाया अतिरिक्त बोझ, शिक्षा पर हो पूरा फोकस

शिक्षा के साथ-साथ चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से लेकर हर क्षेत्र में शिक्षको का उपयोग उनके मूल कार्य को छुड़वा कर करवाया जाता रहा है। वही बच्चों की शिक्षा व्यवस्था वेसे भी चरमराई हुई रही है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कोरोना के कारण शिक्षा के घटे स्तर को वापस लाने के लिए शिक्षकों पर से अतिरिक्त कार्य के बोझ को हटा कर पूरा फोकस केवल शिक्षा पर करवाया जाता है, तो सम्भव है पिछले सत्र की भरपाई भी की जा सकती हैं। वही शिक्षकों पर भी परिणाम देने और पूरे शिक्षण समय संस्था में उपस्थित रहने के सख्ती से निर्देश दिए जाने चाहिए। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण हो चुके अतिथि शिक्षकों की भर्ती बड़े स्तर पर अच्छे वेतनमान पर कर शिक्षा के क्षेत्र में हुई शिक्षकों की कमी से उभार कर अच्छी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ रिटायर्ड हो चुके शिक्षकों को अतिथि शिक्षक के रूप में उनकी सहमति अनुसार भर्ती पढ़ाई या फिर स्कूल की कागजी कार्यवाही करने के लिए भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि संस्था के मूल शिक्षकों उनका मूल कार्य करवाने का पूरा समय और सहयोग मिले। यदि समय रहते सरकार ने शिक्षा नीति पर गहन मंथन नहीं किया तो भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम बेहत ही परेशान कर देने वाले होंगे।

निजी स्कूलों की लूट सरकार के नियंत्रण से बाहर

कोरोना काल में शिक्षा के बीते दो सत्र में निजी स्कूलों ने बता दिया की उनका शिक्षा से कोई लेना देना नही है। वो केवल व्यापार करने के लिए शिक्षा की दुकान सज़ा कर बैठे हैं, जिसकी दुकान की सजावट जितनी बड़ी उसकी शिक्षा उतनी ही महंगी। कोरोना में जहाँ सरकारी स्कूलों में बिना किसी फीस के प्रमोशन मिला वही निजी स्कूलों ने अपनी लूट जारी रखी और गिने चुने स्कूलों को छोड़ कर बाकी निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस वसूलने के सरकारी आदेश की आड़ में अच्छी खासी फीस वसूल की। इस दौरान बच्चों के परिजनों पर ऑनलाइन शिक्षा का अतिरिक्त बोझ डाला गया, जिससे बच्चे कोई ज्ञान नहीं ले सके उल्टा मोबाइल के आदि हो गए। जिन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की उनको परीक्षा में नही बैठने, रोलनंबर व अंकसूची नहीं देने, फेल करने और टीसी नहीं देने तक कि धमकी देकर मोटी फीस वसुली गई। कई परिवार इस कोरोना काल में भारी संकट से जूझते रहे लेकिन अछि शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए निजी स्कूलों की मोटी फीस मजबूर होकर जमा करनी पड़ी। इस दौरान कई आवाज़े भी उठी मामला विधानसभा तक उठा अखबारों की सुर्खियों में आया लेकिन सरकार के नियंत्रण से बहार या फिर कहे सरकार की मौन स्वीकृति ने निजी स्कूलों की वसूली पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। नए सत्र के शुरु होते ही ये निजी स्कूल अपनी फीस में मनचाही बढ़ोत्तरी के साथ अतिरिक्त खर्चों के साथ-साथ स्कूल ड्रेस, किताबों, बस किराया के नाम पर बड़ी वसुली शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि निजी स्कूलों की इस लूट पर लगाम लगाकर फीस के साथ-साथ सभी निजी स्कूलों में एक तरह की किताबें और पाठ्यक्रम को सुनिश्चित किया जाए। ड्रेस ओर सिलेबर्स को कम से कम 4-5 वर्षों तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। परमार जी आप झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री के साथ उच्च शिक्षा (स्वतं प्रभार) मंत्री का महत्व पूर्ण दायित्व भी है। आप देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चो के हित में संज्ञान लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएंगे यह उम्मीद सभी को है।